



# सम्पादकीय

## ਮਰ्ज बढ़ाती कोताही

जुलाई की शुरुआत से दुधारू पशुओं को गिरफ्त में लेने वाले लपी त्वचा रोग से निपटने में विभिन्न सरकारों ने जैसी हीला-हवाली की उसका नतीजा है कि पशुपालक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। समय रहते इसके उपचार को गंभीरता से न लेने का ही परिणाम है कि देश के कई राज्यों के पशु इस रोग से मर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुधाऊ पशुओं ने दूध देना कम कर दिया है। हालत यह है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व जम्मू-कश्मीर में हजारों जानवर इस रोग की चपेट में फँहूँ हैं। रोग की चपेट में आने वाले पशुओं में गायें ज्यादा हैं। यदि अधिकारी राज्यों की सीमाओं पर सख्ती बरतते तो इस रोग का अंतर्राज्यीय स्तर पर प्रसार न होता। फिलहाल तो डेरी उद्योग से जुड़े किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। बताते हैं कि यह रोग जहां गायों की दूध देने की क्षमता में कमी जाता है, वहीं प्रजनन क्षमता पर भी प्रतिकूल असर डालता है।

शर्वों का निपटान वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो पा रहा है। कई जगह जानवरों के शब्द खुले में पड़े रहते हैं। घोर कुप्रबंधन का आलम यह है कि पशुपालक ने जानवरों के शर्वों को नदी—नहरों में फेंक जाते हैं। बताया जाता है कि अप्रक्ले पंजाब में ही चार हजार से अधिक पशु मर चुके हैं और 75 हजार इस रोग से पीड़ित हैं। निस्संदेह, इस बड़ी चुनौती से मुकाबले को बहुकोणीय नजरिये से युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। जहां तुरंत उपचार व रोग की रोकथाम के लिये अतिरिक्त धन की मंजूरी जरूरी है, वर्हीं पशु विकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सकों व कर्मचारियों की उपलब्धता की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही वैकल्पिक वैक्सीन किसानों की सहज पहुंच में होनी चाहिए। पशु पालकों को जागरूक करने तथा रोग के प्रसार को रोकने के वैज्ञानिक उपायों के बारे में बताना भी जरूरी है। बहरहाल, इस संक्रामक रोग से हालात इतने बेगड़ गये हैं कि समाज में स्वास्थ्य व पर्यावरणीय संकट की चुनौती पैदा हो रही है। इस रोग के चलते चुनौतियों की एक शृंखला उत्पन्न हुई है। वर्हीं पशु चिकित्सकों की कमी से समस्या और विकट हो रही है। इस रोग से जुड़े अनुसंधान के बाद पता लगाया जाना चाहिए कि रोग की रोकथाम के लिये जो वैकल्पिक वैक्सीन दी जा रही है क्या वह स्वस्थ पशुओं को रोग से बचाने में कारगर है। दरअसल, विशेषज्ञों की सलाह के बावजूद अफवाहें फैलायी जा रही हैं कि रोग के चलते गाय का दूध पीना नुकसानदायक हो सकता है। इस बाबत समाज में प्रगतिशील सोच बनाये जाने की जरूरत भी है। साथ ही वैज्ञानिकों की आवाज को प्रभावी बनाने की भी आवश्यकता है। वर्हीं इस संक्रामक रोग ने पिछले एक दशक में जानवरों को दफनाने के लिये आरक्षित थानों को खुर्द-बुर्द करने के संकट को भी उजागर किया है। अवैध कब्जों के चलते इसमें लगातार संकुचन हुआ है।

का सुलझान का काशशा का था। अब 20–22 साल के अंतराल के बाद जम्मू-कश्मीर का मसला और उलझ चुका है। तीन साल पहले मोदी सरकार ने यहां का भू-राजनैतिक परिदृश्य एक फैसले से बदल दिया। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू-कश्मीर के सारे विशेषाधिकार खत्म हो गए। कश्मीर के विलय के बाद भारत सरकार द्वारा किया गया वादा खत्म हो गया। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया और लद्दाख इस राज्य से अलग एक नया केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इसके बाद नए सिरे से परिसीमन का काम भी खत्म हो गया है, जिसके बाद निर्वाचन के हालात भी बदल जाएंगे। कश्मीर जब तक है, तब तक कश्मीरियत तो बनी ही रहेगी, लेकिन इंसानियत और जम्मूरियत की रक्षा का सवाल अब भी अहम बना हुआ है, जिस पर सरकार को सोचना होगा। पिछले चार सालों से जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है और प्रशासन एक तरह से केंद्र



रहा है। विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का काम खत्म होते ही सुगबुगाहट थी कि इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ—साथ जम्मू—कश्मीर में भी चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव अगले साल हो सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों के अलावा नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी जैसे दल भी अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा फैसला हुआ है जिससे भाजपा पर उंगलियां उठने लगी हैं कि वह सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। दरअसल जम्मू—कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने घोषणा की कि गैर—स्थानीय लोग, जिनमें कर्मचारी,

एक सीट शामिल है। अब कश्मीर की 47 और जम्मू की 43 सीटें हैं, माना जा रहा है कि परिसीमन का फायदा भाजपा को मिलेगा। अब अगर राज्य में बाहरी मतदाताओं को चुनाव का हिस्सा बनाया जाएगा, तो यह भी भाजपा की फायदा उठाने की रणनीति का हिस्सा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। 20 लाख से अधिक नए मतदाताओं के जुड़ने का मतलब है कि अब करीब एक करोड़ लोग मतदान में हिस्सा लेंगे। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुप्ती ने तो साफ कहा है कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। भाजपा के लिए जम्मू-कश्मीर एक प्रयोगशाला बन गया है। बाहरी लोगों को जम्मू-कश्मीर के चुनाव में वोट डालने की इजाजत देने का फैसला

तत्कालीन राजनीतिक दलों ने अपने निहित स्वार्थों के लिये मानवता की कीमत सिर्फ़ को ही चुकानी प



रगों कि साप्रदायिक सकौणताएँ अनवता के लिये कितना बड़ा अभिशाप हैं। जो आपराधिक तत्वों को हिंसक दृष्टि करने और स्वच्छंद व्यवहार करने का अवसर देती हैं। यह भी कि

नवहन नहा किया। हमारा आजादी के लिये इन लाखों लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई, वह कल्पना से परे की बात है। सदियों से स्थापित जड़ों से उखड़कर कई पीढ़ियों से अर्जित चल-अचल संपत्ति को कुछ ही क्षणों में गंवाना किसी वज्रपात से कम नहीं था। वजह सिफ यह कि धार्मिक संकीर्णताओं ने हैवानियत की आग में धी डालने का काम किया। निस्संदेह, इस त्रासदी के मूल में ब्रिटिश हुकमरानों की साजिश भी शामिल थी, जो भारतीय आजादी को विफल बनाने की साजिश कर रहे थे। बद्रदाल आजादी के 75 हम पड़ासों नहीं बदल सकत। 21वीं सदी में दोनों देशों और सभी संप्रदायों को सोचना होगा कि हमारी संकीर्ण सोच के चलते मानवता ने कितनी बड़ी कीमत चुकायी है। यह उदाहरण है कि सांप्रदायिक धर्मीकरण की राजनीति कितनी घातक होती है। जिन लाखों लोगों ने अपने घर-बार, परिवार और चल-अचल संपत्ति गवांई, उनकी कभी न खत्म न होने वाली टीस बार-बार इस जहरीली सोच की हकीकत बताती है।

निस्संदेह सांप्रदायिकता की राजनीति

नहीं सभावनाओं का परामर्श हाता ह। किसी भी तरह का संघर्ष व तनाव मनुष्यता के स्वाभाविक विकास में बाधा का ही है। ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है जो जन्म से एक जैसे ही होते हैं। लेकिन धार्मिकता की संकीर्णताएं इंसान में विभाजन के बीज बो देती हैं। निःसंदेह, धर्म व्यक्ति का निजी व्यवहार है। उसकी सीमा वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ दूसरे की आरथा शुरू होती है। सीमाओं का यही अतिक्रमण मानवता के लिये अभिशाप बनता है। कभी कहा जाता रहा है कि स्पृहादायिकता का घाटक प्रभाव अपेक्षा

# वास्तुक आपूत न बढ़े नाक



कि भारत गुणवत्तापूर्ण और किफायती उत्पादों के निर्यात के लिहाज से एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। साथ ही भारत सस्ती लागत के विनिर्माण में चीन को पीछे छोड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि इस समय दुनियाभर में मेक इन इंडिया की मांग बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में मैन्युफैक्चरिंग के तहत 24 सेक्टर को प्राथमिकता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। चूंकि अभी भी देश में दर्वाई उद्योग, मोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरण उद्योग, वाहन उद्योग तथा इलेक्ट्रिक ऐसे कई उद्योग बहुत कुछ चीन से

सरकार ने प्रोडक्शन लिंकड इनसेटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत 13 उद्योगों को करीब दो लाख करोड रुपए आवंटन के साथ प्रोत्साहन सुनिश्चित किए हैं। अब देश के कुछ उत्पादक चीन के कच्चे माल का विकल्प बनाने में सफल भी हुए हैं। पीएलआई योजना के तहत देश में 520 अरब डॉलर यानी लगभग 40 लाख करोड रुपए मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन का जो लक्ष्य है, वह धीरे-धीरे आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएलआई योजना के तहत कुछ निर्मित उत्पादों के निर्यात भी दिखाई देने लगे हैं। इस समय

दो ध्रुवों के बीच विभाजित दिखाई दे रही है। ऐसे में यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारत दोनों ही ध्रुवों के विभिन्न देशों में विदेश व्यापार—कारोबार बढ़ाने की जोरदार संभावनाएं रखता है। इस समय जब रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमले के मद्देनजर पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी, यूरोपीय और जापानी कंपनियों सहित कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा रूस में अपना कारोबार बंद कर गया दिया है, तब रूस में भारत की उपभोक्ता कंपनियों से लेकर दवा निर्माण कंपनियों ने अपना आर्थिक फ्रमवक (आईपीईएफ) के सदस्य देशों की 11 जून को पेरिस में आयोजित हुई अनौपचारिक बैठक के बाद इसके सदस्य देशों के साथ भारत के विदेश व्यापार को नई गतिशीलता मिलने की संभावनाएं उभरकर दिखाई दी हैं। वस्तुतरु आईपीईएफ पहला बहुपक्षीय करार है जिसमें भारत शामिल हुआ है। इसमें अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूद्देश्वर, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इसी वर्ष 2022 में यूरोपीय देशों के साथ किए गए नए आर्थिक समझौतों के क्रियान्वयन से भी भारत

महत्वपूर्ण निर्णय से जहां भारतीय निर्यातकों और आयातकों को अब व्यापार के लिए डॉलर की अनिवार्यता नहीं रहेगी, वहीं अब दुनिया का कोई भी देश भारत से सीधे बिना अमेरिकी डॉलर के व्यापार कर सकता है। ऐसे में उन देशों के साथ भारत के लिए तेजी से कारोबार बढ़ाने के नए मौके निर्मित होंगे। खासतौर से डॉलर संकट का सामना कर रहे रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, पश्चिमा और अफ्रीका सहित कई छोटे-छोटे देशों के साथ भारत का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ेगा। निश्चित रूप से आरबीआई के इस कदम से भारतीय रूपए को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकार करवाने की दिशा में मदद मिलेगी। जिस तरह चीन और रूस जैसे देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने की दिशा में सफल कदम बढ़ाए हैं, उसी तरह अब आरबीआई के निर्णय से भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के कारण रूपए को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिल सकती है और इससे भारत के लिए विदेश व्यापार के नए मौके बढ़ेंगे। हम उम्मीद करें कि इस समय चीन—ताइवान के बीच तनातनी और रूस—यूक्रेन युद्ध की बढ़ती अवधि की चुनौती तथा चीन पर वैश्विक निर्भरता में कमी आने के बीच आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन के मद्देनजर भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एवं विदेश व्यापार बढ़ाने के जो अभूतपूर्व मौके निर्मित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें मुदिरयों में लेने के लिए सरकार और देश के उद्योग-व्यापार जगत के

# कश्मीर-संभल कर बढ़ने की जरूरत

चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए लिया गया है। इसका असली कासद स्थानीय लोगों की ताकत कम करना और जम्मू-कश्मीर पर बरदस्ती शासन करना है। वर्षीय पूर्व रख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता अब्दुल्ला ने पूछा है कि क्या भाजपा जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं ने लेकर इस कदर असुरक्षित महसूस कर रही है कि उसे चुनाव जीतने के लिए बाहर से मतदाताओं का आयात करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसलों से भाजपा को गोई फायदा नहीं होगा। चुनाव की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में अभी से निर्वाचन में विवरदर्शिता को लेकर संदेह का माहौल नना सुखद संकेत नहीं हैं। भाजपा ने हमेशा दावा किया है कि उसके लिए फैसले कश्मीरियों के हितों को दान में रखकर लिए जाते हैं। अब भाजपा को अपने ये दावे सच साबित करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीर में फिर से हसा का माहौल बन रहा है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी तो नहीं हो पाई है, बल्कि अब उन्हें फिर से मारे जाने का डर सताने लगा है। आतंकवादी घटनाएं फिर से जोर पकड़ने लगी हैं, जिसमें निशाने पर सुरक्षा बल और आम नागरिक दोनों ही हैं। जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। अब बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार मिलने के बाद लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी समूह कश्मीर फाइटर्स ने आतंकी हमले तेज करने की धमकी दी है। इस संगठन ने ऐलान किया है कि हर गैर कश्मीरी चाहे वह व्यापारी हो, कर्मचारी हो या भियारी हो, उसे निशाने पर लेना है। बेशक हमारे सुरक्षा बल आतंकवाद का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के नागरिक भी शांति बहाली की प्रक्रिया में पूरा सहयोग देते हैं, क्योंकि अमन की कीमत उनसे बढ़कर कोई नहीं समझ सकता।

घटनाओं के स्मरण तुला :- कल्पनाओं

से ना को पढ़ रखना पूरा का आलोचना का अपने मनोबल पर असर ना पड़ने दें। ग्रहों की अनुकूलता प्रगति के अच्छे अवसर प्रदान करेगी।

**बृष्टि:**— योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दविधारस्त होगा।

पाठ्यक जनता के जुलूम पलन का प्रयत्न करें। शिक्षा-प्रतियोगिता के दिशां में परिश्रम तीव्र होगा। कुछ नई सफलताएं सुखों का आगाज करेंगी।

**वृश्चिक:**— आसीम प्रतिभाओं के बाजार भी हीन मन प्रतिभाओं के

**बिरेधियों** प्रबलता से कार्य क्षेत्र में कठिनाईयाँ संभव। जीविका क्षेत्र में नए आयाम उत्साहित करेंगे।

**मिथुन** :- दूसरों की सफलता से अपने अन्दर हीन भावना ना पाले। नौकरी का वातावरण थोड़ा अरुचिकर

लाभ से वच्चित होगा, अत इसे सुधारें। नैतिक-अनैतिक सोचने वाला मन भौतिक परिवेश ताल-मेल बिटाने में असमर्थ होगा।

**धनु** :- दूसरों की बात इधर से उधार करना आपका शोभा नहीं देता

**कर्क** :- प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण आरंभ करने से पहला शब्द है। इसका अर्थ यह है कि किसी विषय के बारे में ज्ञान लेने के बाद उसका अध्ययन करना। इसका अर्थ यह है कि किसी विषय के बारे में ज्ञान लेने के बाद उसका अध्ययन करना।

कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का भरपूर लाभ उठाने का समय आ गया है। रोजगार में समस्याओं से होतोत्साहित ना हों।

**कुन :-** कृष्णार्थ जाकोदार जपना सार्थकता हेतु आपको उद्देलित करेंगी। निर्थक दसरों की पीठ पीछे

**प्रयत्न तीव** कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे। आलोचना ना करें। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा।

**कन्या** :- रोजगार के क्षेत्र में नए अवसर उत्साह का संचार करेंगे, परन्तु अपने पांच दिनों के लिए जाग नहीं रखें।

**मीन** :- कोई महत्वपूर्ण आकांक्षा अपनी सार्थकता हेतु आपको उद्देशित नहीं है। अपनी चारों ओर से बहुत अचूक और अपेक्षित विद्युत धूमधारी दिखेंगे।

हानिकारक हो सकता है। जो बीत गयी उसे भूल वर्तमान में जीने की चेष्टा करें।

## अन्याय सा न्याय, इसाफ का —त्रैयी ता चौथी तो —

आजादी के पर्व के दिन एक रिहाई ऐसी भी सामने आई जिसने देष में बड़े विवाद लो हवा दे दी। ऐसी रिहाई जिस पर तमाम सवाल उठे। गुजरात में हुए 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गौंग रेप व परिजनों की हत्या के मामले में इसके दो साल अधिकारों ने विराफ़त दे दर्क अंदरी सर्वों तो उस विवाद

कसाठा पर भा हा खरा  
के पर्व के दिन एक रिहाई ऐसी भी सामने आई जिसने देश में बड़े फैलाव दे दी। ऐसी रिहाई जिस पर तमाम सवाल उठे। गुजरात में हुए

जाट रहे ग्यारह अभियुक्तों की रिहाई ने कई गंभीर प्रज्ञों को जन्म दिया। 1 जनवरी, 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने संगीन आरोपों के लिये ग्यारह अभियुक्तों को उम्रकौद की सजा सुनाई थी। कालांतर बॉम्बे ईर्कोर्ट ने सजा पर अपनी सहमति की मोहर लगाई थी। दरअसल, 15 साल और अधिक की जेल की सजा काटने वाले एक दोशी ने विगत में सजा माफी के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सजा माफी के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद चमहल के कलेक्टर के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जिसने कैदियों की रिहाई की मांग पर विचार किया। समिति ने सर्वसम्मति से कैदियों को रिहाई दरने का निर्णय किया। ये सिफारिष राज्य सरकार को भेजी गई थी। कालांतर दोशियों को रिहा करने के आदेश दिये गये। इस पर गुजरात के अतिरिक्त मुख्य विचार का कहना था कि जेल में चौदह साल पूरे होने पर उम्र, अपराध की प्रकृति व कैदियों के व्यवहार आदि पर विचार करने के बाद सजा में छूट देने पर विचार किया गया। साथ ही यह भी देखा जाता है कि अपराधी ने अपनी सजा माफी कर ली है। तभी रिहाई पर विचार किया जा सकता है। कैदी के गंभीर रूप में बीमार होने पर भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है। इस पर मानवाधिकार वर्गकर्ताओं का आरोप है कि इससे कम गंभीर मामलों में सजा पाने वाले कैदी व दोशियों में बंद हैं जबकि गंभीर अपराध में लिप्त दोशियों को रिहा कर दिया गया है। इस फैसले से बिलकिस बानों का परिवार सकते में है और उनका कहना है कि वे फिर से भय में जी रहे हैं। दरअसल, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमें ग्यारकार ने इस मामले में कोई सूचना नहीं दी, हमें मीडिया से दोशियों की रिहाई की बात पता चली। वहीं गुजरात सरकार के इस फैसले की चौतरफा आलोचना भी रही है। कहा जा रहा है कि अपराध के विकार लोगों का तंत्र पर भरोसा डिगिटल विभाग द्वारा है। दरअसल, बिलकिस बानो ने न्याय पाने के लिये लंबा संघर्ष किया था। पहले ग्यूरूओं के अभाव में पुलिस ने केस खारिज कर दिया था। गुजरात सरकार के द्वारा जब उसे न्याय मिलता न दिखा तो वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हुंची। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिये। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कलोजर रिपोर्ट खारिज की गई। सीबीआई ने चार्जीषिट 18 लोगों को दोशी पाया था। लगातार धमकी मिलने और न्याय मिलने में दोहे के चलते बिलकिस बानो ने केस गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने की चाचा लाख का मुआवजा, घर व नौकरी देने का भी आदेश दिया था। जिस पर गुजरात सरकार के वकीलों ने सवाल भी उठाये थे। दोशियों की रिहाई से बिलकिस बानो स्तब्ध है, वह कहती है कि उनका वर्षा का संघर्ष व मेहनत कार कि वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो को दो सप्ताह के भीतर चाचा लाख का मुआवजा, घर व नौकरी देने का भी आदेश दिया था। जिस पर गुजरात सरकार के वकीलों ने सवाल भी उठाये थे। दोशियों की रिहाई से बिलकिस बानो स्तब्ध है, वह कहती है कि उनका वर्षा का संघर्ष व मेहनत कार चली गई। गुजरात सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस समेत तमाम दल पक्षी दल हमलावर हैं। कांग्रेस कह रही है कि एक तरफ केंद्र सरकार नारी सम्मान की बात करती है तो दूसरी ओर एक महिला के साथ जघन्य अपराध दरने वालों को रिहा कर देती है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से न्याय की दूसरी



